

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा वभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1229
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

दिल्ली विश्व विद्यालय में निधि की कमी

†1229.श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या दिल्ली विश्व विद्यालय वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में 462 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, जब कि वगत वर्ष यह घाटा 248 करोड़ रुपये था और यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवर्ती व्ययों में वृद्धि को देखते हुए विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आवंटन को उसी हिसाब से नहीं बढ़ाया गया और विश्व विद्यालय को व्यय को पूरा करने के लिए कुछ हद तक छात्रों के शुल्क में वृद्धि करनी पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो वगत तीन वर्षों के दौरान विश्व विद्यालय के व्यय में हुई वृद्धि और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान छात्रों के शुल्क में हुई बढ़ोतरी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) दिल्ली विश्व विद्यालय की वित्तीय संकट की समस्या को हल करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा मंत्रालय "केन्द्रीय विश्व विद्यालयों को अनुदान" के अंतर्गत विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को एकमुश्त अनुदान जारी करता है जो दिल्ली विश्व विद्यालय (डीयू) सहित केन्द्रीय विश्व विद्यालयों (सीयू) को उनकी आवश्यकताओं, पछले वर्ष के दौरान किए गए व्यय के साथ-साथ निधियों की उपलब्धता के आधार पर धनराशि आवंटित करता है। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, पछले तीन वर्षों के दौरान वेतन और आवर्ती शीर्षों के अंतर्गत दिल्ली विश्व विद्यालय को दिए जाने वाले अनुदानों में लगातार वृद्धि की गई है। इसके अलावा, दिल्ली विश्व विद्यालय द्वारा इस मंत्रालय को निधि घाटे के कारण शुल्क में वृद्धि की

ऐसी कसी घटना की सूचना नहीं दी गई है। यूजीसी ने वत्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक दिल्ली वश्व वद्यालय को 821 करोड़ रुपये की धनराश के आवंटन की सूचना दी है।

दिल्ली वश्व वद्यालय संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है जो अपने स्वयं के, अधिनियमों, संवधियों, अध्यादेशों और वनियमों आदि द्वारा शासित होता है और वश्व वद्यालय स्वतः शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों के साथ-साथ फस में वृद्ध के मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।
